

F-11014/1/2015-Water-II-Part(5)
Government of India
Ministry of Drinking Water & Sanitation

4th Floor, Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi, 110003

Dated 1st ^{April} ~~March~~, 2016

To

Principal Secretaries/ Secretary
(in charge of Rural Drinking Water Supply)
All State Govts.

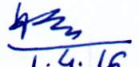
Subject :- Zero leakage in Rural and Urban Water Supply Schemes.

Sir,

This Ministry has received some of the media reports pointing out that 50% potable drinking water gets wasted because of leakages before it reaches to the consumer and this condition is worse in rural areas.

It is apparent that use of cheap and breakable plastic pipes in Public water distribution system is responsible for bulk of leakages.

Since, the country is already facing shortages of drinking water because of erratic monsoon and contaminated water in many of the regions, it is requested to take suitable measures to prevent / check leakage of water by using appropriate quality of pipes.


(A.K. Srivastava)
Under Secretary (Water)

Copy to :- Shri Aayush Kumar, Convenor, Save Water Society, 58/5, Birhana Road, Kanpur, Pin – 208001.

- 85820 -



प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office

नई दिल्ली- 110011
New Delhi- 110011

Sub:Petition of SHRI AYUSH KUMAR
SAVE WATER SOCIETY
58/5 BIRHANA ROAD
KANPUR NAGAR
UTTAR PRADESH

A letter/gist of oral representation dated 14/02/2016 received in this office from SHRI AYUSH KUMAR is forwarded herewith for action as appropriate. Reply may be sent to the Petitioner and a copy of the same may be uploaded on the portal.

[V.B.Hariharan]
Section Officer

SECRETARY,MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

PMO ID No.:PMOPG/D/2016/0047170 Dated: 23/02/2016

PMOPG/10/2016/0047170

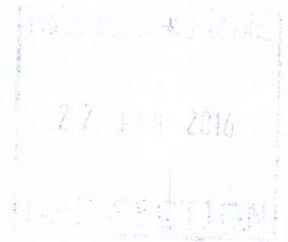
129

Save Water Society

58/5, Birhana Road, Kanpur-203001 Ph: 0512-3012764 email : savewatersociety@gmail.com
Convenor : Ayush Kumar

14.2.16.

The Prime Minister of India,
Govt. of India,
7, Race Course Road,
New-Delhi-110001.



Sub: Policy for Zero leakage in Rural and Urban Water Supply Schemes.

According to Research Reports from Singapore, in Indian cities about 50% potable water leaked before it reaches consumer (copy enclosed). In Rural areas conditions are much worse.


Bulk of the leakages is due to use of cheap and breakable plastic pipes (PVC/HDPE) in potable water distribution system. If we use metallic pipe in water distribution, we may reduce this leakage to bare minimum. These metallic pipes are available in India easily.

We request you to announce a policy for zero leakage in rural/urban potable water supply schemes.

The Central Govt. and State Govts together invest about 20000 Crores every year for providing safe drinking water to its people. If we achieve zero leakage we may increase the availability of potable water by 100% without any further investment through this Policy.

With kind regards,

Yours truly,
For Save Water Society,


(Ayush Kumar)

M. to DWS
8/

नीतियों और तरीकों में हो सुधार



अरिच के विरोध
कमलेंद्र प्रसाद सिंग
कृषि विभाग के सचिव और
पब्लिक रिलीज, रायपुर



सेशिलिया टेरटाजादा
सोमियर रिजर्व फेलो, ली
कृष्ण रेव स्कूल ऑफ
पब्लिक रिलीज, रायपुर

एक आधुनिक संघ में जापान ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2016 तैयार करने के लिए दुनिया भर के 750 विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों की अवधि में उत्पन्न होने वाले सबसे बड़े वैश्विक खतरों की संभावना और प्रभावों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने 29 प्रमुख खतरों का उनके महत्त्व के आधार पर आकलन किया। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के समय को गैर-जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की मौजूदा सबसे बड़े वैश्विक संकट के रूप में पहचान की गई और जल संकट को तीसरे सबसे बड़ी समस्या बताया गया। यदि अगले 10 वर्षों में संगठित प्रभावों के आधार पर विचार किया जाए तो 40 प्रतिशत विशेषज्ञों ने जल संकट और 37 प्रतिशत ने जलवायु परिवर्तन को चर्चा किया।

भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। देश में उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के चिन्ह दिखते हैं। राजको से इस्तेमाल की जा रही कमजोर नीतियों और तौर-तरीकों के कारण खासी देशों की तुलना में भारत की जलवायु स्थिति बदतर है। वरिष्ठ नीति निर्धारकों में इस मामले पर सख्त संधि सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखती। नभीर बाद और सूखे के दौरान ही राजनेताओं की इस ओर संचि दिखती है। इन आपदाओं के समाप्त होते ही वह संधि भी समाप्त हो जाती है। समाज कार्य के चलते देश में जल की मांग आने आने दिनों में कई गुना बढ़ने के संकेत हैं। इन परिस्थितियों में यदि देश पहले से चले की अन्वेषण-विकास और पर-विकासक जल प्रबंधन नीतियों को व्यवहार में लाता है तो अगले 10-20 वर्षों में उसे भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि देश की जलवायु दशाओं के इतना प्रभाव होने की आशंका नहीं दिखती। जल, गैस और गंधी खनिजों की तुलना में जल नवीकरणीय ससाधन है। सही प्रबंधन के साथ पानी का एक बार उपयोग होने के बाद संचि कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा ज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन के तौर-तरीकों और समस्त क्षेत्रों में सक्षम उपयोग के साथ अगले कई दशकों तक सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के पास भरपूर जल है। कमजोर प्रबंधन की खामी के रूप में देश के शहरी जल प्रबंधन का-हाल देखा जा सकता है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां रातों रात, 24 घंटे पानी की सप्लाई होती हो और बिना स्वास्थ्य खिता के भीसे नल ही टोटी से पानी पिया जा सके। इस कारण हर शहरी चर्चक नल-जल

भारतीय शहरों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले समस्त जल का 40-50 प्रतिशत हिस्सा लीकेज और जल प्रबंधन के कारण बेकार चला जाता है। नोन चिन्ह में यह नुकसान प्रति 6-7 प्रतिशत है। इस तिहाज से भारत भले ही उपभोक्ता दुई आर्थिक शक्ति हो लेकिन इसके शहरी जल प्रबंधन तौर-तरीके नाम फेर-संसाधन विकसित शहरों से पीछे है।

भारत को अपनी मौजूदा लचक जल प्रबंधन नीतियों और तौर-तरीकों को सुधारना ही होगा। यह संभव है और इसके अलावा देश के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

संचर का भेज है। एक दिन में कुछ घंटे ही पानी मिलने के कारण वे घर में लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टैंकों में पानी एकत्र करते हैं। 10 साल पहले यरो में साधारण फिल्टर से पानी का शोधन किया जाता था। अब जल की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि बड़ी संख्या में परिवार सिविल ऑस्मोसिस (आरओ) का इस्तेमाल करते हैं। यरो जलापूर्ति मुक्त है या इस पर अन्वेषण-विकास है। यरो में एक ऐसा उपयुक्त विज्ञान मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जहां प्रचलित तरीके को संचित संचिनी सुविधा मिले जहाँ संचि उपयोग किए जल और उसके खराब जल के शोधन की पूरी चर्चात तो जाए।

हालांकि अतिरिक्त एक बड़ी समस्या देश के समाप्त यह है कि शहरी क्षेत्रों के भीतर या निकट लगभग सभी जल निष्का अन्वेषिक प्रवृत्ति है। केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की 445 शहरों में से तकनीक आनी जैविक यंत्र-पदार्थों और को-बो-वर्क वैक्यूमिरी का बजट से अत्यधिक प्रवृत्ति है। यदि अन्य पदार्थको मसाले गहू-टेट, पलोचड, खतरनाक ससाधन और भारी धातुओं की दृष्टि से देखा जाए तो देश की किसी भी नरी का पानी बिना संचन शोधन के पीने योग्य नहीं है। गंगा और यमुना नदी की सप्लाई के लिए सरकार के पैकडों करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं। भारत की जलवायु समस्याओं का समाधान संभव है। इसके लिए भारत राजनीतिक इच्छा, भजवत जल सस्थानों के निर्माण और सरकारी धन का सक्षम तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। जगत को भी स्वीकार करना होगा कि जलवायु तभी बेहतर जल सुविधाएं सिद्धी जल उपभोक्ता-विकास और टैबलों के माध्यम से वे लागत का लाभ देंगे। इसके अतिरिक्त और कई अन्य विकल्प नहीं हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार उपाय नहीं किए गए तो वैश्विक रूप से अगले दो दशकों के भीतर अविश्वसनीय जल संकट से ज्ञाना होगा।